

जा रहे ब्याज की राशि उनसे अर्जित शुद्ध लाभ की राशि से भी अधिक है; यदि हाँ, तो ब्याज की राशि कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) 31-3-1990 तक केवल इसी अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 244 उद्यमों में कुल 99315.31 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया था। 233 चालू उद्यम हैं जिनमें 93091.08 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया है तथा शेष 11 उद्यम निर्माणाधीन चरण में हैं।

(ग) 1989-90 के दौरान 233 चालू उद्यमों द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ की राशि 3781.73 करोड़ रुपये है जो पूंजीनिवेश का 4.06 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र के भिन्न-भिन्न उद्यमों में 1990-91 से संबंधित लेखे तैयार किये जाने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) जी हाँ। 1989-90 के दौरान 60358.17 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋणों पर 4245.39 करोड़ रुपये का ब्याज देय था।

#### Threat to suspend the release of new films

719. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that producers of motion pictures have threatened to suspend the release of all new films in the country in protest against the arbitrary price hike of 37.5 per cent imposed by Government run-Hindustan Photo Films on cine picture raw stock; and

(b) if so, what steps Government propose to take in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) and (b) The film industry had represented against the price revision of Colour Positive film announced by Hindustan Photo Films (HPF) with effect from

15-6-91. The price revision of Cine Colour Positive has for the time being kept in abeyance for reviewing the matter in detail.

720. [Transferred to 2nd August, 1991]

#### Privatisation of public sector undertakings

721. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering to privatise some public sector undertakings in the country;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to issue any white paper in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

#### Indigenous technologies developed by C.S.I.R.

722. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of the indigenous technologies developed by the C.S.I.R. laboratories during the last three years;

(b) whether any action has been taken by Government so far to promote their utilisation by the Indian industries; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) Details of the major technologies developed by the CSIR laboratories during the last 3 years i.e. 1988-91. are given below:

i. zeolite additives (developed by National Chemical Laboratory but not yet commercialised).

ii. food grade hexane (developed by Indian Institute of Petroleum and licensed to two parties).

(iii) cyanoacrylate and pressure sensitive adhesives (developed by Indian Institute of Chemical Technology and since productionised).

iv. pheromones (developed by Indian Institute of Chemical Technology and since productionised).

v. ethanol from molasses (developed by National Chemical Laboratory and since commercialised).

vi. ferromagnetic chromium dioxide (developed by National Aeronautical Laboratory, negotiations for commercialisation are in progress).

vii. bricks from fly ash (developed by Central Fuel Research Institute and since productionised).

viii. improved oil expeller (developed by Mechanical Research and Development Organisation and since commercialised).

ix. automatic weather station (developed by National Institute of Oceanography, negotiations with potential users are in progress).

x. flexible graphite tapes and sheets (developed by National Chemical Laboratory and since commercialised).

xi. biological rope contractor (developed by National Environmental Engineering Research Institute and since commercialised).

xii. palm oil extraction developed by Regional Research Laboratory, Trivandrum and pilot plant set up).

(b) and (c) Yes, Sir. Both the CSIR and National Research Development Corporation (NRDC) have established mechanisms to publicise the technologies available to industry. CSIR has further interaction with industry organisations and industrial units to promote the use of its technologies.

समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की शीर्षक का  
आवंटन

723. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम  
अफजल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का एक बार शीर्षक का आवंटन कर दिये जाने के बाद, किसी भी दशा में (चाहे उस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो जाए, या उसके स्वामी की मृत्यु हो जाती है) उसका आवंटन किसी दूसरे समाचार पत्र/पत्रिका को नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या जो व्यक्ति नई पत्रिका प्रकाशित करना चाहते हैं उन्हें ऐसी स्थिति में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है और इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय से उपमंत्री (कुमारी पारजा व्यास) : (क) जी, हाँ। तथापि किसी आवेदक को शीर्षक का आवंटन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तब किया जाता है जब भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा यह सत्यापित कर दिया जाता है कि शीर्षक अमूक आवंटन के लिये उपलब्ध है।

(ख) मालिक द्वारा की गई घोषणा को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधि-प्रमाणित कर दिए जाने के बाद वह शीर्षक उस मालिक की संपत्ति बन जाता है। वह शीर्षक मालिक द्वारा अथवा उसके मालिक की मृत्यु के पश्चात् कानूनी उत्तर धिकारी द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। प्रकाशन बंद हो जाने की मूरत में, मालिक द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष नई घोषणा दाखर करने के बाद उसे फिर से शुरू किया जा सकता है।

(ग) नए आवेदकों को कठिन इयां होती हैं लेकिन जब कभी विशिष्ट शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं तो उनका जांच की जाती है।